



NaMo 25 · #25YearsofSeva

GYAN · गरीब · युवा · अन्नदाता · नारी

ज्ञान — चार सबसे बड़ी जातियाँ

प्रधानमंत्री के शब्दों में देश की चार सबसे बड़ी जातियाँ हैं — गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन चारों के लिए 25 साल का लेखा-जोखा, अलग-अलग: हर आँकड़े के साथ तिथि।

7 अक्टूबर 2001 → 7 अक्टूबर 2026 · 25 साल, ज़ीरो ब्रेक · 25YearsofSeva.com · संस्करण 88 · 7 अक्टूबर 2026
हर आँकड़ा तिथि सहित — पूरा रिकॉर्ड वेबसाइट पर।



24.82 करोड़

लोग गरीबी से बाहर आए

2013-14 से 2022-23 के बीच (रिपोर्ट 15 जनवरी 2024)

81 करोड़+

लोगों को मुफ्त राशन

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से, मार्च 2020 से

4.21 करोड़

पक्के घर (2014–2024)

पीएम आवास योजना — शहरी और ग्रामीण मिलाकर

10.57 करोड़

मुफ्त गैस कनेक्शन

उज्ज्वला योजना से, 1 मई 2016 से (सितम्बर 2026 तक)

59.37 करोड़

जन धन बैंक खाते

28 अगस्त 2014 से — हर परिवार बैंक से जुड़ा (सितम्बर 2026)

15.91 करोड़

गाँव के घरों में नल से पानी (82%)

जल जीवन मिशन से, 15 अगस्त 2019 से (अगस्त 2026)

60 करोड़+

लोगों को ₹5 लाख तक मुफ्त इलाज का कवर

आयुष्मान भारत से, 23 सितम्बर 2018 से

12 करोड़+

शौचालय बने

स्वच्छ भारत मिशन से, 2 अक्टूबर 2014 से

51 लाख करोड़+

रुपये सीधे खातों में

सरकारी सहायता बिना बिचौलिये के — जन धन, आधार और मोबाइल से



पड़ाव — तिथिवार

28 अगस्त 2014

जन धन योजना

पहले ही सप्ताह में करोड़ों खाते खुले; सितम्बर 2026 तक 59.37 करोड़ खाते हैं और सरकारी लाभ सीधे इन्हीं में पहुँचता है।

2 अक्टूबर 2014

स्वच्छ भारत मिशन

गांधी जयंती पर शुरू हुए अभियान से 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने और गाँव खुले में शौच से मुक्त घोषित हुए।

1 मई 2016

उज्ज्वला योजना

बलिया से शुरू हुई योजना ने 10 करोड़ से अधिक परिवारों को धुएँ से मुक्ति दी; 10 करोड़वाँ कनेक्शन 30 दिसम्बर 2023 को अयोध्या में दिया गया।

25 सितम्बर 2017

सौभाग्य

सौभाग्य योजना ने हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुँचाया और 28 अप्रैल 2018 को देश का हर गाँव बिजली से जुड़ गया।

23 सितम्बर 2018

आयुष्मान भारत

राँची से शुरू हुई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना 60 करोड़ से अधिक लोगों को ₹5 लाख तक का निशुल्क उपचार देती है; 29 अक्टूबर 2024 से 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक बिना आय-सीमा के इसमें शामिल हैं।

15 अगस्त 2019

जल जीवन मिशन

लाल किले से हर घर नल से जल की घोषणा हुई; अगस्त 2026 तक लगभग 16 करोड़ (82%) ग्रामीण परिवार नल से जुड़ चुके हैं।

मार्च 2020

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

कोविड के संकट में शुरू हुई निःशुल्क अनाज की योजना 81 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुँची; एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से प्रवासी कहीं भी राशन ले सकते हैं।

2015

पीएम आवास योजना

शहरी और ग्रामीण घटकों से 2014 से 2024 के बीच 4.21 करोड़ पक्के घर बने, जिनमें अधिकांश महिलाओं के नाम या संयुक्त नाम पर हैं।

2020

पीएम स्वनिधि

रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी कार्यशील पूँजी मिली — मई 2026 तक 1.12 करोड़ से अधिक ऋण — और पहली बार औपचारिक ऋण तक उनकी पहुँच बनी।

2.35 लाख+

पंजीकृत स्टार्टअप

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम (जून 2026)

1.6 करोड़+

युवाओं को कौशल प्रशिक्षण

पीएम कौशल विकास योजना से, 2015 से

81 → 38

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान

2015 से 2025 के बीच — 43 स्थान ऊपर

10,000 +

अटल टिकटिंग लैब

स्कूलों में बच्चों के लिए इनोवेशन की प्रयोगशालाएँ

36,441 करोड़

₹

खेलो इंडिया 2.0 का बजट (2026-31)

मंजूरी 31 जुलाई 2026 को

4.5 करोड़+

परीक्षा पे चर्चा 2026 में पंजीकरण

2025 में 3.53 करोड़ — गिनीज विश्व रिकॉर्ड

107

पदक — एशियाई खेल 2023

अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन; पैरालंपिक 2024 में 29 पदक

10,372 करोड़

₹

रुपये का इंडिया एआई मिशन

फरवरी 2026 में नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट हुई

2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

34 वर्ष बाद नई नीति — मातृभाषा, कौशल और रचनात्मक सोच पर जोर

पड़ाव — तिथिवार

1 जुलाई 2015

डिजिटल इंडिया

सस्ते डेटा, यूपीआई और डिजिटलॉकर ने युवा भारत को दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाज़ार बनाया।

15 जुलाई 2015

स्کیل इंडिया

स्کیل इंडिया मिशन शुरू हुआ (मंत्रालय 9 नवम्बर 2014 को बना) और पीएम कौशल विकास योजना से 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिला।

16 जनवरी 2016

स्टार्टअप इंडिया

कर छूट, फंड ऑफ फंड्स और सरल पंजीकरण से जून 2026 तक 2.35 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप बने, जिनमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं।



2016

अटल इनोवेशन मिशन

नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन से स्कूलों में 10,000 से अधिक अटल टिकरिंग लैब खुलीं, जहाँ छठी कक्षा से ही रोबोटिक्स और 3डी प्रिंटिंग सिखाई जाती है।

2017-18

खेलो इंडिया

खेलो इंडिया ने स्कूल से विश्वविद्यालय तक खेल प्रतियोगिताएँ और छात्रवृत्तियाँ दीं; भारत ने टोक्यो 2020 में 7, एशियाई खेल 2023 में 107 और पैरालंपिक 2024 में 29 पदक जीते।

29 जुलाई 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

34 वर्ष बाद आई नई नीति ने मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा, बहुविषयक पढ़ाई और कौशल पर ज़ोर दिया।

17 सितम्बर 2023

पीएम विश्वकर्मा

पीएम विश्वकर्मा योजना 18 पारम्परिक व्यवसायों के कारीगरों को प्रशिक्षण, औज़ार और बिना गारंटी ऋण देती है; सितम्बर 2026 तक 30 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हुए।

31 अक्टूबर 2023

मेरा युवा भारत

मेरा युवा भारत युवाओं के लिए स्वयंसेवा, कौशल और नेतृत्व के अवसरों का राष्ट्रीय मंच बना।

2024

पीएम इंटरशिप

पीएम इंटरशिप योजना देश की शीर्ष कंपनियों में युवाओं को इंटरशिप का अवसर देती है; रोजगार मेलों से लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले।

4.46 लाख करोड़+

रुपये पीएम-किसान से सीधे खातों में

24 फरवरी 2019 से 23 किस्ते; 23वीं किस्त 2.18 करोड़ महिला किसानों को भी मिली

3,765 लाख टन

अनाज का उत्पादन

2025-26 में — अब तक का रिकॉर्ड (तीसरा अग्रिम अनुमान)

1.3 लाख करोड़ ₹

रुपये — कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट 2026-27

₹1,30,561 करोड़ — 2013-14 के ₹21,933 करोड़ से लगभग छह गुना

1.8 करोड़+

किसान ऑनलाइन मंडी ई-नाम से जुड़े

2016 से; 1,656 मंडियाँ भी जुड़ीं

10,000

किसान उत्पादक संगठन (FPO)

लक्ष्य फरवरी 2026 में पूरा — छोटे किसानों की सामूहिक ताकत

266.50 ₹/ बैग

रुपये में यूरिया का बैग — किसान के लिए दाम स्थिर

45 किलो का बैग; बाकी लागत सरकार सब्सिडी से देती है

59,261

सहकारी समितियाँ (पेक्स) कंप्यूटर से जुड़ीं

दिसम्बर 2025 तक; लक्ष्य 79,630

1.98 करोड़ टन

मछली का उत्पादन 2024-25

2013-14 के 0.95 करोड़ टन से दोगुने से अधिक

2003-04

मिट्टी की जाँच के कार्ड की शुरुआत

गुजरात में शुरू हुए; 2015 में राष्ट्रीय योजना बने

पड़ाव — तिथिवार

2003-04 → 2015

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

2003-04 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू की गई योजना 19 फरवरी 2015 को राष्ट्रीय योजना बनी, जिससे हर खेत की मिट्टी की रिपोर्ट किसान के हाथ में पहुँची।

18 फरवरी 2016

पीएम फसल बीमा

13 जनवरी को मंज़ूर और 18 फरवरी को शुरू — कम प्रीमियम पर फसल की सुरक्षा मिली, ताकि प्राकृतिक आपदा में किसान अकेला न रहे।

14 अप्रैल 2016

ई-नाम

राष्ट्रीय कृषि बाज़ार से मंडियाँ ऑनलाइन जुड़ीं; मार्च 2026 तक 1.8 करोड़ से अधिक किसान और 1,656 मंडियाँ इससे जुड़ चुकी हैं।

2018

लागत का डेढ़ गुना एमएसपी

बजट 2018-19 से समर्थन मूल्य (MSP) उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुने पर तय होता है।

24 फरवरी 2019

पीएम-किसान

हर वर्ष ₹6,000 सीधे खाते में पहुँचते हैं; 23 किस्तों में अब तक ₹4.46 लाख करोड़ से अधिक किसानों तक पहुँचे।

2019

पीएम-कुसुम

खेत पर सौर पंप और सौर ऊर्जा से किसान बिजली का उत्पादक भी बना।



2020

10,000 किसान उत्पादक संगठन

छोटे किसानों को बाज़ार की सामूहिक ताकत देने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य फरवरी 2026 में पूरा हुआ।

2023

श्री अन्न — अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष

भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया।

नवम्बर 2024

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

रसायन-मुक्त खेती के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू हुआ; सिक्किम देश का पहला शत-प्रतिशत जैविक राज्य है।

3 करोड़+

लखपति दीदी

2029-30 तक 6 करोड़ लखपति दीदी का संकल्प

10 करोड़+

महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों में

91 लाख से अधिक समूह

49 %+

मुद्रा ऋण महिलाओं को मिले

कुल 57.79 करोड़ ऋणों में से (मार्च 2026)

33 %

सीटें महिलाओं के लिए — लोकसभा और विधानसभाओं में

नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 28 सितम्बर 2023

105 करोड़+

सैनिकी पैड 11 में

जन औषधि केंद्रों से बिके

80 लाख+

किशोरियों को मुफ्त एचपीवी टीके

28 फरवरी 2026 से अभियान (सितम्बर 2026 तक)

15,000

नमो ड्रोन दीदी

स्वयं सहायता समूहों की महिलाएँ ड्रोन उड़ा रही हैं

26 सप्ताह

वेतन सहित मातृत्व अवकाश

2017 से — दुनिया के सबसे लम्बे अवकाशों में से एक

2019

तीन तलाक का अंत

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून, 31 जुलाई 2019

पड़ाव — तिथिवार

22 जनवरी 2015

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ · सुकन्या समृद्धि

पानीपत से शुरू हुए अभियान और बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि बचत योजना ने गुजरात की कन्या केलवणी (2003) की परम्परा को राष्ट्रीय रूप दिया।

2015–16

मुद्रा और उज्ज्वला

मुद्रा (अप्रैल 2015) के ऋण खातों में लगभग 68% महिलाओं के हैं (पीआईबी, 2025) और उज्ज्वला (मई 2016) के 10.57 करोड़ कनेक्शन महिलाओं के नाम पर दिए गए।

2017

26 सप्ताह मातृत्व अवकाश

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम ने सवैतनिक अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया।

31 जुलाई 2019

तीन तलाक कानून

तत्काल तीन तलाक को अवैध और दंडनीय बनाकर मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी गई।

2020

सेना में स्थायी कमीशन

महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिला; 2021 से सैनिक स्कूल और 2022 से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी बेटियों के लिए खुले।

2021–22

मिशन शक्ति

संबल और सामर्थ्य उप-योजनाओं के साथ मिशन शक्ति सुरक्षा, आश्रय और सशक्तिकरण की एक समग्र योजना है।

28 सितम्बर 2023

नारी शक्ति वंदन अधिनियम

यह अधिनियम लोकसभा में 454–2 और राज्यसभा में 214–0 से पारित हुआ; एक-तिहाई आरक्षण जनगणना के बाद परिसीमन के साथ लागू होगा।

2023

लखपति दीदी · नमो ड्रोन दीदी

स्वयं सहायता समूहों की 3 करोड़ से अधिक महिलाएँ लखपति दीदी बनीं और 15,000 समूहों को ड्रोन दिए जा रहे हैं।

2024

शौचालय, नल और गैस — गरिमा की त्रयी

12 करोड़ शौचालयों, लगभग 16 करोड़ नल कनेक्शनों और 10.5 करोड़ गैस कनेक्शनों का सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिला।